PIONEER, Delhi, 5.6.2025
Page No. 2, Size:(3.20)cms X (9.80)cms.

SC issues notice to MP on scribes' plea alleging assault by cops

PIONEER NEWS SERVICE ■ New Delhi

The Supreme Court on Wednesday sought Madhya Pradesh Government's response on a plea of two journalists who were thrashed by police for reporting on illegal sand mining activities.

A bench of Justices Sanjay Karol and Satish Chandra Sharma, however, refused to grant interim protection from arrest to them.

The bench agreed to hear the pleas of Shashikant Goyal and Amarkant Singh Chouhan, and issued notices to Madhya Pradesh and the NCT of Delhi for their responses and posted the matter on June 9.

The counsel appearing for the petitioners pressed for interim protection but the court said, "Let the other side respond. Let the facts be brought by the state also. We are listing it on Monday (June 9)."

The top court asked why the petitioners did not make the superintendent of police of Bhind a party to the petition.

"It is very easy to say all kinds of things against an IPS officer without making him a party. Whatever comes to your mind, just put it in black and white against the IPS officer," it added.

The bench also asked why the National Human Rights Commission (NHRC) and the NCT of Delhi were made parties.

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 5.6.2025
Page No. 5, Size:(2.92)cms X (10.20)cms.

एनएचआरसी ने शर्मिष्ठा मामले में मुख्य सचिव व डीजीपी को भेजा नोटिस

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार इंटरनेट मीडिया एंफ्लुएंसर व कानून विषय की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। शर्मिष्ठा इस वक्त कोलकाता की अलीपुर महिला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। शर्मिष्ठा को दुष्कर्म व हत्या की धमकियां मिल चुकी हैं। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा-'हमें लीगल राइट्स आब्जर्वेटरी नामक संगठन से शिकायत मिली है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के समय उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। शर्मिष्ठा को धमकियां मिलने की भी जानकारी दी गई है। इसे देखते हुए हमने बंगाल के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक व डीजीपी को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।'

मालूम हो कि शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने गत 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उनके विरुद्ध वजाहत खान कादरी रशीदी नामक व्यक्ति ने गत 15 मई को कोलकाता में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस बीच शर्मिष्ठा के पिता ने शर्मिष्ठा के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की प्रति प्राप्त न होने का आरोप लगाया है।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 5.6.2025
Page No. 11, Size:(2.54)cms X (9.83)cms.

दो पत्रकारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दो पत्रकारों की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अवैध रेत खनन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर पुलिस ने उनकी पिटाई की थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इन्कार कर दिया है।

पीठ ने शशिकांत गोयल व अमरकांत सिंह चौहान की याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए मध्य प्रदेश और दिल्ली को उनके जवाब के लिए नोटिस जारी किए तथा मामले की अगली सुनवाई नौ जून को तय की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अंतरिम संरक्षण की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को जवाब देने दें। राज्य को भी तथ्य पेश करने दें। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने भिंड के पुलिस अधीक्षक को याचिका में पक्ष क्यों नहीं बनाया। पीठ ने कहा, किसी आइपीएस अधिकारी को पक्ष बनाए बिना उसके खिलाफ हर तरह की बातें कहना बहुत आसान है। पीठ ने यह भी पूछा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दिल्ली को पक्ष क्यों बनाया गया है।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 5.6.2025
Page No. 11, Size:(2.54)cms X (7.77)cms.

शर्मिष्ठा पनौली की सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है।

नोटिस में पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार इंटरनेट मीडिया एंफ्लुएंसर व कानून विषय की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। शर्मिष्ठा अभी न्यायिक हिरासत में हैं। शर्मिष्ठा को दुष्कर्म व हत्या की धमकियां मिल चुकी हैं। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा-हमें लीगल राइट्स आब्जर्वेटरी नामक संगठन से शिकायत मिली है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। इसे देखते हुए बंगाल के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।

TIMES OF INDIA, Ahmedabad, 5.6.2025
Page No. 22, Size:(8.63)cms X (15.97)cms.

Prez Murmu terms stampede 'shocking and heartbreaking'

New Delhi: President Droupadi Murmu on Wednesday expressed deep sorrow over the loss of lives in a stampede near the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, and called the incident 'shocking and heartbreaking'.

She offered her condolences to the families of those who died and wished a quick recovery for the injured.

In a social media post on X, Droupadi Murmu wrote, "The loss of lives in the tragic happening at a stadium in Bengaluru is shocking and heartbreaking. My condolences to the bereaved families and prayers for the speedy recovery of the injured." Trinamool Congress (TMC) MP Abhishek Banerjee said he is shocked and saddened by the stampede at Bengaluru's Chinnaswamy Stadium.

He offered condolences to the families of those who lost their lives and wished a speedy recovery to the injured.

"Shocked and saddened by the tragic stampede at Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. My thoughts and prayers are with the families who have lost their loved ones in this unimaginable tragedy," in a post, Banerjee wrote.

Footwears lie on the ground following the stampede

"Wishing strength and a speedy recovery to all those who are injured. May the departed souls rest in peace and may their families find comfort in this difficult time," the post reads.

While National Human Rights Commission (NHRC) member Priyank Kanoongo said the death of innocent people in the stampede during IPL victory celebrations in Karnataka is quite painful.

He assured that the matter is being taken seriously, and strict action will be taken after the investigation. ANI

PIONEER, Lucknow, 5.6.2025
Page No. 8, Size:(10.77)cms X (33.64)cms.

SC issues notice to MP on scribes' plea alleging assault by cops

PIONEER NEWS SERVICE ■ New Delhi

The Supreme Court on Wednesday sought Madhya Pradesh Government's response on a plea of two journalists who were thrashed by police for reporting on illegal sand mining activities.

A bench of Justices Sanjay Karol and Satish Chandra Sharma, however, refused to grant interim protection from arrest to them.

The bench agreed to hear the pleas of Shashikant Goyal and Amarkant Singh Chouhan, and issued notices to Madhya Pradesh and the NCT of Delhi for their responses and posted the matter on June 9.

The counsel appearing for the petitioners pressed for interim protection but the court said, "Let the other side respond. Let the facts be brought by the state also. We are listing it on Monday (June 9)."

The top court asked why the petitioners did not make the superintendent of police of Bhind a party to the petition.

"It is very easy to say all kinds of things against an IPS officer without making him a party. Whatever comes to your mind, just put it in black and white against the IPS officer," it added.

The bench also asked why the National Human Rights Commission (NHRC) and the NCT of Delhi were made parties.

AMAR UJALA (MY CITY), Fatehabad, 5.6.2025
Page No. 3, Size:(12.09)cms X (8.59)cms.

कानूनगो ने सुनीं 23 शिकायतें, 15 का समाधान, आठ पर दिल्ली से कार्रवाई

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक ने भूना में लगाया जनता दरबार, सुनीं लोगों की शिकायतें

संवाद न्यूज एजेंसी

भूना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बुधवार को गुरु दक्ष प्रजापति धर्मशाला में जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत जनता दरबार लगाया। इसमें नागरिकों की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में कुल 23 शिकायतें आईं, इनमें से 15 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। आठ शिकायतों पर कानूनगो ने दिल्ली जाकर कार्रवाई का भरोसा दिया।

जनता दरबार में टोहाना के कुलभूषण सिंगला ने शिकायत देते हुए कहा कि डीएसपी, एसपी और डीजीपी को शिकायत देने के बावजूद भी उन पर जानलेवा हमला करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। उन्होंने डीएसपी, एसपी फतेहाबाद और डीजीपी ऑफिस तक सबूत दिए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई।

भूना में गुरु दक्ष प्रजापति धर्मशाला में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के समक्ष शिकायत रखती महिला। संवाद

जांडलीखुर्द गांव के रोहताश कुमार और उनकी पत्नी ने भी शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई और गांव की एक लड़की ने प्रेम विवाह किया। इसके बाद गांव के दबंगों ने उनके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर गांव से निकाल दिया। जबकि उनका प्रेमी जोड़े से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उनके घर में आग लगा तोड़फोड़ की गई और बूढ़े पिता की पिटाई की गई।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने दबंगों के दबाव में आकर मामले को दबा दिया। प्रियंक कानूनगो ने इस मामले में भी दोबारा कार्रवाई का आश्वासन दिया। थानाध्यक्ष सुरेंद्र ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा विवरण कानूनगो के सामने रखा।

गोल्ड मेडलिस्ट दो महिला खिलाड़ी की सम्मानित

साउथ कोरिया में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में गोल्ड मेडलिस्ट पूजा प्रजापति व कबड्डी में गोल्ड मेडलिस्ट रितु को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बधाई दी और आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने दोनों बेटियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम के संयोजक और राष्ट्रीय बाल आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने कानूनगो का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कानूनगो ने पिछड़ा वर्ग की समस्याएं सुनीं और उन्हें जागरूक किया। कार्यक्रम में कुम्हार सभा के प्रधान जिले सिंह जाखड़, भीम सिंह झींझर, पार्षद सुशील सोनी, रोहतास गोयल, नरेश सोनी, प्रकाश कुमार आदि मौजूद रहे।

DAINIK JAGRAN, Siliguri, 5.6.2025
Page No. 7, Size:(5.34)cms X (10.48)cms.

एनएचआरसी का शर्मिष्ठा की सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस

- शर्मिष्ठा अलीपुर महिला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं
- पिता ने पुलिस पर प्राथमिकी की प्रति नहीं देने का आरोप लगाया

राज्य ब्यूरो, जागरण● कोलकाता : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को नोटिस जारी कर पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार इंटरनेट मीडिया एंफ्लुएंसर व कानून विषय की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। शर्मिष्ठा इस वक्त कोलकाता की अलीपुर महिला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। शर्मिष्ठा को दुष्कर्म व हत्या की धमकियां मिल चुकी हैं। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा-'हमें लीगल राइट्स आब्जर्वेटरी नामक संगठन से शिकायत मिली है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के समय उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। शर्मिष्ठा को धमकियां मिलने की भी जानकारी दी गई है। इसे देखते हुए हमने बंगाल के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक व डीजीपी को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।' शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस की टीम ने गत 30 मई को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। उनके विरुद्ध वजाहत खान कादरी रशीदी नामक व्यक्ति ने गत 15 मई को कोलकाता के गार्डेनरीच थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इस बीच शर्मिष्ठा के पिता पृथ्वीराज पनौली ने बंगाल सरकार व पुलिस के उस दावे को सिरे से नकारा है कि उनकी बेटी गिरफ्तारी से पहले गुड़गांव से फरार हो गई थी। उन्होंने पुलिस पर शर्मिष्ठा के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की प्रति नहीं देने का भी आरोप लगाया है।

वजाहत को गिरफ्तार करने कोलकाता आ रही असम पुलिस की टीम

वजाहत को गिरफ्तार करने असम पुलिस की एक टीम कोलकाता आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में तीन पुलिसकर्मियों की टीम इस बाबत बुधवार को गुवाहाटी से रवाना हुई है। कोलकाता पहुंचकर वह वजाहत को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी। वजाहत पर मां कामाख्या के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में असम पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने वजाहत को कानूनी कार्रवाई के लिए असम लाने में बंगाल सरकार से सहयोग करने को कहा है।

Free Press Journal

NHRC India Hosts Statutory Full Commission Meeting To Strengthen Synergy Among Human Rights Bodies For Enhanced Protection Of Vulnerable Communities

The National Human Rights Commission (NHRC), India organized a Statutory Full Commission meeting of all 7 deemed member Commissions and Chief Commissioner for Persons with Disabilities in New Delhi today. The meeting aimed to enhance synergy and cooperation among the Commissions to promote and protect human rights.

https://www.freepressjournal.in/india/nhrc-india-hosts-statutory-full-commission-meeting-to-strengthen-synergy-among-human-rights-bodies-for-enhanced-protection-of-vulnerable-communities

Somendra Sharma | Updated: Wednesday, June 04, 2025, 05:24 PM IST

The National Human Rights Commission (NHRC), India organized a Statutory Full Commission meeting of all 7 deemed member Commissions and Chief Commissioner for Persons with Disabilities in New Delhi today. The meeting aimed to enhance synergy and cooperation among the Commissions to promote and protect human rights.

Chairing the meeting, Justice Shri V. Ramasubramanian, Chairperson, NHRC, India emphasised the importance of collaborative functioning among the Commissions. He suggested convening joint meetings of Statutory Full Commission members at regular intervals and creating a mechanism to hyperlink the websites of all Commissions to avoid duplication of cases.

NHRC, India holds Statutory Full Commission Meeting. May like to refer to the press release
at: https://t.co/YbJVRW6RYZ@PIBHomeAffairs @PIB_India @ANI @PTI_News @airnewsalerts @DDNewslive #NHRCIndia #HumanRights pic.twitter.com/rzLgtaqMBF

— NHRC India (@India_NHRC) June 3, 2025

The meeting discussed various issues, including the protection of rights of vulnerable and marginalized sections, sharing best practices, and minimising duplication of cases. The participants emphasised the need for joint fact-finding missions, awareness campaigns, and outreach programmes.

Shri Kishor Makwana, Chairperson, National Commission for Scheduled Caste (NCSC) spoke about proactive measures taken by the Commission for the rights and welfare of the SC communities.

Smt Vijaya Rahatkar, Chairperson, National Commission for Women (NCW) said that NCW has been focusing on complaints, research, awareness and outreach training programmes for the welfare of women.

Smt Tripti Gurha, Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) emphasised on running awareness campaigns to stop child trafficking and to ensure faster legal remedies in POSCO cases.

Speaking on the occasion, Shri Nirupam Chakma, Member, National Commission for Scheduled Tribes, Shri Rajesh Aggarwal, Chief Commissioner, Commission for Persons with Disabilities and Shri Daniel E. Richards, representing the National Commission for Minorities also shared their perspectives and made arguments in favour of having a joint mechanism between the sectoral commissions for addressing human rights issues of the vulnerable communities.

Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi, Member, NHRC, India, emphasised the importance of ensuring that welfare schemes reach all sections of society, including the marginalised. NHRC, India Member, Smt Vijaya Bharathi Sayani remarked that these Commissions are not isolated institutions but a co-traveller working towards promoting and protecting human rights.

Earlier, setting the agenda for the meeting, Shri Bharat Lal, Secretary General, NHRC, India gave an overview of the unique institutional human rights protection framework of the country. He emphasised that such interactions among these institutions are useful in forming a common platform on key issues of human rights and collectively ensure quick relief to the victims.

Shri Samir Kumar, Joint Secretary, NHRC, India summarized the activities undertaken by the Commission over the last year. The meeting concluded with a renewed commitment to collaborative efforts among the Commissions to promote and protect human rights in India.

The Indian Express

SC seeks response from Madhya Pradesh, Delhi home depts on `harassment of 2 journalists' by Bhind police

Shashikant Jatav and Amarkant Chouhan have sought to prevent the MP Police from taking coercive action against them. On May 28, the Delhi HC granted police protection to Chouhan.

https://indianexpress.com/article/india/sc-response-madhya-pradesh-delhi-home-depts-harassment-journalists-bhind-police-10047689/

Written by Sohini Ghosh | New Delhi | Updated: June 4, 2025 14:49 IST

4 min read

The Supreme Court Wednesday sought responses from the home departments of Madhya Pradesh and Delhi in a petition by two journalists from Bhind who are seeking "urgent protection" after allegedly facing assault, caste-based abuse, and harassment at the hands of the MP Police for "exposing corruption" through their reports.

Before the apex court, the two journalists – Shashikant Jatav and Amarkant Singh Chouhan – have sought a direction to the MP Police against taking any coercive action against them. In their plea, they also sought protection for themselves. The bench admitted the matter and posted it next for consideration on June 9.

The bench of Justices Sanjay Karol and Satish Chandra Sharma on Wednesday expressed that it wants the facts brought on the court's record by the state before it decides to provide relief to the journalists by way of interim protection from coercive action. The bench also assured that it will come to the petitioners' rescue if there is a threat to life.

On May 28, the Delhi High Court had granted Delhi Police protection to Chouhan who was allegedly harassed, threatened, and stripped inside a police station in Madhya Pradesh's Bhind earlier that month. This protection still continues.

At the time, while Chouhan's petition had sought that the high court call for a status report from the MP Police into the incident, the court had orally opined that it would be appropriate to pursue the remedy before the Madhya Pradesh High Court instead. Jatav too had a petition pending before the Delhi High Court, which has not been taken up and has been renotified for consideration on July 14.

Chouhan and Jatav had fled to Delhi on May 19 after allegedly facing harassment from the MP Police, and had thereafter filed complaints with the National Human Rights Commission (NHRC) and the Press Council of India (PCI). Further impressing on the threat from the state police, the journalists informed the top court that on May 28, when Chouhan's petition was being heard, the Bhind police were camping outside the Delhi High Court campus.

The petitioners alleged that in May, Chouhan and Jatav were “invited” to have a cup of tea with Asit Yadav, Superintendent of Police (SP), Bhind, at his chambers where “they were physically assaulted and battered by (the SP)…and his subordinates.” It was claimed that more than half a dozen other journalists were also present in the SP Asit Yadav’s chamber, who had all been stripped down to their undergarments before being physically assaulted and battered prior to their arrival.

As per the journalists, “SP Asit Yadav was displeased about the extensive reporting about the illegal sand mining activities in the Chambal river that are carried out by the sand mafia in connivance with the local police.”

On May 4, Chouhan and Jatav were on their way from Gwalior to Delhi to meet MP Jyotiraditya Scindia and “apprise him of their plight” when they were “picked up by one Saurabh Sharma, another journalist, on the pretext of going to Delhi by road”, they stated. The two were, instead, allegedly taken to a nearby dhaba where some police officials were waiting, who took the two journalists to SP Yadav’s bungalow to work out a ‘compromise’, warned that they should no longer pursue the matter of being assaulted by Bhind police officers on May 1, and told to drop the charges.

On May 5, they were once again summoned by SP Yadav to his office, “where they were forced to record a video statement in the presence of other police officials, stating that all matters between them and the police have been “resolved”,” the petition states. The video was then circulated by the Bhind police through WhatsApp with the intention of destroying the credibility of the two journalists, it contends.

The Week

SC issues notice to Madhya Pradesh on scribes' plea alleging assault by cops

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/06/04/lgd9-sc-journalists-ld-mp.html

PTI Updated: June 04, 2025 17:25 IST

New Delhi, Jun 4 (PTI) The Supreme Court on Wednesday sought Madhya Pradesh government's response on a plea of two journalists who were allegedly thrashed by police for reporting on illegal sand mining activities.

A bench of Justices Sanjay Karol and Satish Chandra Sharma, however, refused to grant interim protection from arrest to them.

The bench agreed to hear the pleas of Shashikant Goyal and Amarkant Singh Chouhan, and issued notices to Madhya Pradesh and the NCT of Delhi for their responses and posted the matter on June 9.

The counsel appearing for the petitioners pressed for interim protection but the court said, "Let the other side respond. Let the facts be brought by the state also. We are listing it on Monday (June 9)."

The top court asked why the petitioners did not make the superintendent of police of Bhind a party to the petition.

"It is very easy to say all kinds of things against an IPS officer without making him a party. Whatever comes to your mind, just put it in black and white against the IPS officer," it added.

The bench also asked why the National Human Rights Commission (NHRC) and the NCT of Delhi were made parties.

The counsel said NHRC was made a party as petitioners had previously filed a complaint there and offered to remove it as a party from the case.

On the NCT of Delhi, the counsel said both the petitioners were in the national capital at present.

The bench asked why was it not informed on June 2, when the matter was mentioned for urgent listing, about the petitioners moving the Delhi High Court where the matter was pending.

"Why did you not tell us at that point in time that you had already approached the Delhi High Court and the matter was pending?" it asked.

The counsel said the petitioners were seeking a stay on arrest and protection from coercive action in the Supreme Court and such reliefs were not sought in the high court.

"We don't know what kind of a crime has been registered against you by the police.

Can we grant you some blanket kind of anticipatory bail order that you will not be touched even if you commit a crime against this nation? Can we grant this kind of an order?" the bench asked further.

It observed the "phantom" of the story which was created on the day of mentioning was not made out in the petition.

While mentioning the matter on June 2, the bench said, the counsel claimed a threat to the petitioners' lives aside from regular intimidation.

"We believed your phantom of story and we allowed your mentioning. You did not tell us one fact that you have already approached the Delhi High Court," it said.

The counsel referred to the FIR, saying the petitioners hadn't concealed anything from the court.

"We appreciate that you are the fourth pillar. We appreciate also that if there is a threat to life, we will come to your rescue. But you will have to also answer two-three things," the bench said.

The bench enquired about the apprehension of threat to life as claimed by the petitioners and asked what prevented them from moving either the Madhya Pradesh High Court or going back to the Delhi High Court for protection.

The counsel, in the meantime, referred to a press release of the Press Club of India condemning the incident.

When the counsel informed the bench that the petitioners were in the national capital, the bench said, "Today, you don't have an apprehension in Delhi. We will issue notice and list it on Monday".

The bench said, "Suppose you are involved in a case of murder, what to do then? We don't know what is the case against you", when the counsel insisted on grant of interim protection.

"We will hope that since the Supreme Court has issued notice and is seized of the matter, they will not take any coercive steps," the counsel said.

On May 28, the Delhi High Court granted two-month protection to Chouhan, who claimed there was threat to his life by the Bhind superintendent of police after he was allegedly beaten in his office.

The high court directed Delhi Police to provide protection to Chouhan, the Bhind Bureau Chief of Swaraj Express news channel.

"In the meantime, they can approach the high court concerned (for availing further legal remedies)," the high court said.

Three journalists from Bhind district recently alleged that they were beaten and manhandled inside the office of superintendent of police, an allegation denied by the officer.

Pritam Singh Rajawat who runs a YouTube channel, Shashikant Goyal who runs a news portal and Chouhan, alleged in a complaint to the district collector that they were assaulted on May 1.

(This story has not been edited by THE WEEK and is auto-generated from PTI)

Devdiscourse

Supreme Court Seeks MP Government’s Response on Journalist Assault Case

The Supreme Court has asked for the Madhya Pradesh government's response regarding two journalists, Shashikant Goyal and Amarkant Singh Chouhan, allegedly attacked by police while reporting on illegal sand mining. Despite requests, the court denied interim arrest protection, questioning why specific officials and entities weren't directly involved in the petition.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3446828-supreme-court-seeks-mp-governments-response-on-journalist-assault-case

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 04-06-2025 17:13 IST | Created: 04-06-2025 17:13 IST

The Supreme Court has demanded a response from the Madhya Pradesh government concerning allegations that two journalists were assaulted by police officers. This follows complaints from journalists Shashikant Goyal and Amarkant Singh Chouhan, who claim they were targeted for their coverage of illegal sand mining activities.

Despite pleas from the petitioners' counsel for interim protection against arrest, the bench, comprising Justices Sanjay Karol and Satish Chandra Sharma, did not grant such relief. The court questioned why the petition excluded specific officials like the Bhind superintendent of police, while including entities like the National Human Rights Commission and the NCT of Delhi.

The case was further complicated by the petitioners' failure to initially disclose to the Supreme Court their concurrent appeal to the Delhi High Court for related protective measures. The matter is scheduled for further hearing on June 9, with the Supreme Court hoping that no coercive actions will be taken against the journalists in the interim.

(With inputs from agencies.)

The Print

उच्चतम न्यायालय ने मप्र पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाने वाले पत्रकारों की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

https://hindi.theprint.in/india/supreme-court-seeks-response-from-government-on-petition-of-journalists-accusing-mp-police-of-beating-them/826921/

भाषा | 4 June, 2025 08:03 pm IST

नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से उन दो पत्रकारों की याचिका पर बुधवार को जवाब मांगा, जिन्होंने आरोप लगाया है कि अवैध रेत खनन पर रिपोर्टिंग करने के कारण राज्य के एक थाने में उनके साथ मारपीट की गई।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हालांकि दोनों पत्रकारों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की तथा मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नौ जून के लिए सूचीबद्ध की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील ने पीठ से आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए।

पीठ ने कहा, ‘‘दूसरे पक्ष को जवाब देने दीजिए। राज्य को भी तथ्य पेश करने दीजिए।’’

शीर्ष अदालत ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने भिंड के पुलिस अधीक्षक को याचिका में पक्षकार क्यों नहीं बनाया।

पीठ ने कहा, ‘‘किसी आईपीएस अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना उसके खिलाफ हर तरह की बातें कहना बहुत आसान है।’’

पीठ ने यह भी पूछा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पक्ष क्यों बनाया गया।

वकील ने कहा कि एनएचआरसी को पक्षकार बनाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले वहां शिकायत दर्ज कराई थी और मामले से उसे पक्षकार के रूप में हटाने की पेशकश की थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर, वकील ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ता फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में हैं।

पीठ ने पूछा कि दो जून को जब मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किए जाने के बारे में उसे क्यों नहीं बताया गया, जहां मामला लंबित था।

पीठ ने पूछा, ‘‘आपने हमें उस समय क्यों नहीं बताया कि आप पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं और मामला लंबित है?’’

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक तथा दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय से ऐसी राहत नहीं मांगी गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मई को चौहान को सुरक्षा प्रदान की थी। चौहान ने दावा किया था कि भिंड के पुलिस अधीक्षक से उनकी जान को खतरा है, जिनके कार्यालय में उन्हें कथित तौर पर पीटा गया था।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को मध्य प्रदेश निवासी और ‘स्वराज एक्सप्रेस’ समाचार चैनल के भिंड ब्यूरो प्रमुख चौहान को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था।

पिछले महीने भिंड जिले के तीन पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के अंदर उनके साथ मारपीट की गई या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हालांकि पुलिस अधिकारी ने इस आरोप से इनकार किया था।

यूट्यूब चैनल चलाने वाले प्रीतम सिंह राजावत, समाचार पोर्टल चलाने वाले गोयल और समाचार चैनल के लिए काम करने वाले चौहान ने जिला कलेक्टर को सौंपी शिकायत में आरोप लगाया कि एक मई को उनके साथ मारपीट की गई।

भाषा

शफीक सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

Pioneer

SC issues notice to MP on scribes' plea alleging assault by cops

https://www.dailypioneer.com/2025/india/sc-issues-notice-to-mp-on-scribes----plea-alleging-assault-by-cops.html#:~:text=The%20Supreme%20Court%20on%20Wednesday,on%20illegal%20sand%20mining%20activities.

Thursday, 05 June 2025 | Pioneer News Service | New Delhi

The Supreme Court on Wednesday sought Madhya Pradesh Government's response on a plea of two journalists who were thrashed by police for reporting on illegal sand mining activities.

A bench of Justices Sanjay Karol and Satish Chandra Sharma, however, refused to grant interim protection from arrest to them.

The bench agreed to hear the pleas of Shashikant Goyal and Amarkant Singh Chouhan, and issued notices to Madhya Pradesh and the NCT of Delhi for their responses and posted the matter on June 9.

The counsel appearing for the petitioners pressed for interim protection but the court said, "Let the other side respond. Let the facts be brought by the state also. We are listing it on Monday (June 9)."

The top court asked why the petitioners did not make the superintendent of police of Bhind a party to the petition.

"It is very easy to say all kinds of things against an IPS officer without making him a party. Whatever comes to your mind, just put it in black and white against the IPS officer," it added.

The bench also asked why the National Human Rights Commission (NHRC) and the NCT of Delhi were made parties.

The counsel said NHRC was made a party as petitioners had previously filed a complaint there and offered to remove it as a party from the case.

On the NCT of Delhi, the counsel said both the petitioners were in the national capital at present.

The bench asked why was it not informed on June 2, when the matter was mentioned for urgent listing, about the petitioners moving the Delhi High Court where the matter was pending.

"Why did you not tell us at that point in time that you had already approached the Delhi High Court and the matter was pending?" it asked. The counsel said the petitioners were seeking a stay on arrest and protection from coercive action in the Supreme Court and such reliefs were not sought in the high court.

“We don’t know what kind of a crime has been registered against you by the police. Can we grant you some blanket kind of anticipatory bail order that you will not be touched even if you commit a crime against this nation? Can we grant this kind of an order?” the bench asked further.

Jagran

पत्रकारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी; अंतरिम संरक्षण देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दो पत्रकारों की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है जिनमें अवैध रेत खनन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर पिटाई का आरोप है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश और दिल्ली को नोटिस जारी किए और अगली सुनवाई 9 जून को तय की।

https://www.jagran.com/news/national-supreme-court-hearing-on-journalists-plea-notice-to-mp-govt-23956150.html

By Agency Edited By: Swaraj Srivastava Updated: Thu, 05 Jun 2025 12:01 AM (IST)

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दो पत्रकारों की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अवैध रेत खनन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर पुलिस ने उनकी पिटाई की थी।

हालांकि, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इन्कार कर दिया है। पीठ ने शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान की याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए मध्य प्रदेश और दिल्ली को उनके जवाब के लिए नोटिस जारी किए तथा मामले की अगली सुनवाई नौ जून को तय की।

अंतरिम संरक्षण की मांग खारिज

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अंतरिम संरक्षण की मांग की लेकिन कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को जवाब देने दें। राज्य को भी तथ्य पेश करने दें। इस दौरान शीर्ष न्यायालय ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने भिंड के पुलिस अधीक्षक को याचिका में पक्ष क्यों नहीं बनाया। पीठ ने कहा कि किसी आईपीएस अधिकारी को पक्ष बनाए बिना उसके खिलाफ हर तरह की बातें कहना बहुत आसान है।

पीठ ने यह भी पूछा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और दिल्ली को पक्ष क्यों बनाया गया है। वकील ने कहा कि एनएचआरसी को पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले वहां शिकायत दर्ज कराई थी और मामले से उसे पक्षकार के रूप में हटाने की पेशकश की थी। दिल्ली को पक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोनों याचिकाकर्ता वर्तमान में दिल्ली में हैं।

पीठ ने पूछा कि आपने हमें उस समय क्यों नहीं बताया कि आप पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और मामला लंबित है? वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक और बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण की मांग कर रहे थे और हाई कोर्ट में ऐसी राहत नहीं मांगी गई थी।

Tribune India

Will not accept any post-retirement position: CJI Gavai

Will not accept any post-retirement position, says CJI Gavai in UK

https://www.tribuneindia.com/news/india/will-not-accept-any-post-retirement-position-cji-gavai/

Satya Prakash | Tribune News Service | New Delhi, Updated At : 11:56 AM Jun 04, 2025 IST

Barely three weeks into his office, Chief Justice of India BR Gavai has announced that he would not take up any government assignment after he retires on November 23 this year.

“If a judge takes up another appointment with the government immediately after retirement, or resigns from the Bench to contest elections, it raises significant ethical concerns and invites public scrutiny,” the CJI said last evening at a roundtable discussion at the UK Supreme Court on “Maintaining Judicial Legitimacy and Public Confidence”.

He said, “A judge contesting an election for a political office can lead to doubts regarding the independence and impartiality of the judiciary, as it may be seen as a conflict of interest or as an attempt to gain favour with the government.”

CJI Gavai said, “The timing and nature of such post-retirement engagements could undermine the public’s trust in the judiciary’s integrity, as it could create a perception that judicial decisions were influenced by the prospect of future government appointments or political involvement.

“In light of this, many of my colleagues and I have publicly pledged not to accept any post-retirement roles or positions from the government. This commitment is an effort to preserve the credibility and independence of the judiciary,” the CJI said.

In India, judges have a fixed retirement age. While high court judges retire at 62, the retirement age for the Supreme Court judges is 65.

However, many retired judges accept post-retirement roles/positions as many of the laws provide for appointment of retired judges as chairpersons and members of various tribunals and commissions, including the National Human Rights Commission and state human rights commissions.

A controversy erupted in March 2020 when former CJI Ranjan Gogoi accepted his nomination to the Rajya Sabha.

Justice Gogoi headed the five-judge Bench that delivered the Ayodhya verdict. In February 2023, Justice S. Abdul Nazeer who was a part of the five-judge Bench that delivered the Ayodhya verdict was appointed as a Governor of Andhra Pradesh after his retirement as a judge of the Supreme Court. Justice P Sathasivam was appointed

Governor of Kerala in September 2014. In 1978, Justice Mohammad Hidayatullah was elected Vice-President of India.

Talking about the voluntary disclosure of assets by the judges of the Supreme Court, the CJI said it would promote greater accountability and set an example of ethical leadership and bolster public confidence in the institution through transparency.

“To enhance public transparency, the Supreme Court of India also initiated live-streaming of its Constitution-bench cases. However, as with any powerful tool, live streaming must be wielded with care, as fake news or out-of-context court proceedings can negatively shape public perception,” CJI Gavai said.

Mint

CJI Gavai flags ethical concerns over judges entering politics post-retirement, says, `attempt to gain favour with govt'

Chief Justice BR Gavai raised concerns over judges taking government roles post-retirement, highlighting ethical issues and the potential erosion of public trust in the judiciary during a discussion in the UK.

https://www.livemint.com/news/india/cji-gavai-flags-ethical-concerns-over-judges-entering-politics-post-retirement-says-attempt-to-gain-favour-with-govt/amp-11749016896953.html?articleno=1

Livemint | Updated4 Jun 2025, 11:59 AM IST

Chief Justice of India BR Gavai, during a roundtable discussion at the Supreme Court of the United Kingdom, voiced concern about retired judges taking up government appointments or entering electoral politics shortly after stepping down.

As reported by LiveLaw, Gavai remarked that such actions raise significant ethical issues and risk damaging public trust in the judiciary.

CJI Gavai warned that these post-retirement roles could lead to a perception that judicial decisions were made with an eye on future political or governmental opportunities.

"If a judge takes up another appointment with the government immediately after retirement, or resigns from the bench to contest elections, it raises significant ethical concerns and invites public scrutiny. A judge contesting an election for a political office can lead to doubts regarding the independence and impartiality of the judiciary, as it may be seen as a conflict of interest or as an attempt to gain favour with the government," CJI said, as reported by LiveLaw.

He further noted, "The timing and nature of such post-retirement engagements could undermine the public's trust in the judiciary's integrity, as it could create a perception that judicial decisions were influenced by the prospect of future government appointments or political involvement."

CJI Gavai emphasised that he and many of his colleagues had "publicly pledged not to accept any post-retirement roles or positions from the government."

This, he said, was "an effort to preserve the credibility and independence of the judiciary."

His remarks come amid a long-standing debate over whether judges should be eligible for post-retirement positions. This concern has been deepened in recent years by Supreme Court and high court judges taking up roles offered by the executive branch soon after demitting office.

Take a look at post-retirement appointments

Justice Ranjan Gogoi was appointed to the Rajya Sabha in 2020, just four months after retiring as Chief Justice of India. His nomination was controversial due to his involvement in high-profile cases like the Ayodhya verdict and the Rafale deal, which were seen as favourable to the government.

Justice S. Abdul Nazeer was appointed as the Governor of Andhra Pradesh within 40 days of retiring from the Supreme Court. Nazeer was part of the bench that delivered the Ayodhya verdict and upheld the demonetisation policy.

Justice P. Sathasivam was appointed as the Governor of Kerala in 2014, soon after his retirement as Chief Justice of India.

Justice Ranganath Misra, post his retirement as CJI in 1991, was appointed the first Chairperson of the **National Human Rights Commission** in 1993 and later nominated to the Rajya Sabha in 1998.

Justice Baharul Islam retired from the Supreme Court in January 1983 and was nominated to the Rajya Sabha just a few months later—a move that drew criticism as a possible reward for clearing the then Bihar Chief Minister in a corruption case.

Justice M. Hidayatullah served as Vice President of India from 1979 to 1984, nine years after retiring as Chief Justice of India.

If a judge takes up another appointment with the government immediately after retirement, it raises significant ethical concerns and invites public scrutiny.

Justice Fathima Beevi served as a member of the National Human Rights Commission and later as the Governor of Tamil Nadu from 1997 to 2001 after retiring from the Supreme Court in 1992.

Justice M.C. Chagla resigned as Chief Justice of the Bombay High Court in 1958 to become India's Ambassador to the United States at the invitation of former Prime Minister Jawaharlal Nehru.

Hindustan Times

CJI Gavai cautions judges against accepting govt posts, contesting polls

https://www.hindustantimes.com/india-news/cji-gavai-cautions-judges-against-accepting-govt-posts-contesting-polls-101749014277823.html

By Utkarsh Anand | Jun 04, 2025 10:47 AM IST

CJI Gavai warned that such practices raise “significant ethical concerns” and risk eroding public confidence in the judiciary’s independence

Chief Justice of India (CJI) Bhushan R Gavai has sounded a strong note of caution against judges accepting government posts or contesting elections immediately after retirement, warning that such practices raise “significant ethical concerns” and risk eroding public confidence in the judiciary’s independence.

“If a judge takes up another appointment with the government immediately after retirement, or resigns from the bench to contest elections, it raises significant ethical concerns and invites public scrutiny,” underlined CJI Gavai, addressing a high-powered roundtable on judicial independence at the Supreme Court of the United Kingdom on Tuesday.

“A judge contesting an election for a political office can lead to doubts regarding the independence and impartiality of the judiciary, as it may be seen as a conflict of interest or as an attempt to gain favour with the government,” he said.

The CJI said the timing and nature of such post-retirement engagements could undermine the public’s trust in the judiciary’s integrity. He added that it could create a perception that judicial decisions were influenced by the prospect of future government appointments or political involvement.

CJI Gavai emphasised that he and many of his colleagues had “publicly pledged not to accept any post-retirement roles or positions from the government.” This, he said, was “an effort to preserve the credibility and independence of the judiciary.”

His remarks come amid long-standing debate over whether judges should be eligible for post-retirement positions, a concern deepened in recent years by Supreme Court and high court judges taking up roles offered by the executive soon after demitting office.

Justice SA Nazeer, who retired as a Supreme Court judge in January 2023, was appointed as the governor of Andhra Pradesh, within 40 days of his retirement. Justice Nazeer was part of the five-judge bench that decided the Ram Janmabhoomi case in November 2019, handing over the Ayodhya land to the Hindu party. He was the lone Muslim on the Ayodhya bench presided over by then CJI Ranjan Gogoi.

Justice Gogoi was also nominated to the Rajya Sabha four months after retiring as the CJI in November 2019, sparking widespread criticism. Justice Gogoi was the second CJI to become a member of the upper House. Former CJI Ranganath Misra was nominated

to the Rajya Sabha by the Congress and served from 1998 to 2004. Former Supreme Court judge Fathima Beevi was appointed governor of Tamil Nadu (1997-2001). Former CJI P Sathasivam was appointed governor of Kerala (2014-2019). While Justice K Subba Rao contested the fourth Presidential elections, Justice Mohammad Hidayatullah became Vice President from 1979 to 1984.

Similarly, Justice Arun Mishra was appointed chairperson of the **National Human Rights Commission** within a year of retirement. Several high court judges have taken gubernatorial or tribunal posts immediately after leaving the bench.

Judicial misconduct

The CJI acknowledged a deeper malaise afflicting the judiciary, corruption and professional misconduct among judges, which he said severely tarnish the institution's legitimacy. "Sadly, there have been instances of corruption and misconduct that have surfaced even within the judiciary. Such occurrences inevitably have a negative impact on public confidence, potentially eroding faith in the integrity of the system as a whole," he said.

Justice Gavai said that the path to rebuilding this trust lies in the swift, decisive, and transparent action taken to address and resolve these issues. "In India, when such instances have come to light, the Supreme Court has consistently taken immediate and appropriate measures to address the misconduct," he said.

"Transparency and accountability are democratic virtues. In today's digital era, where information flows freely and perceptions are rapidly shaped, the judiciary must rise to the challenge of being accessible, intelligible, and answerable, without compromising its independence."

The CJI did not name anyone. His remarks came against the backdrop of the controversy surrounding high court judge Yashwant Varma. A Supreme Court inquiry panel indicted Justice Varma over unaccounted cash found at his Delhi residence in March. In early May, the then CJI, Sanjiv Khanna, initiated the process for Justice Varma's removal by writing to President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi. Justice Khanna called the cash recovery at the judge's residence serious, warranting the initiation of proceedings for his removal. The development placed judicial accountability under the spotlight, fueling calls for clearer standards and greater transparency.

Legitimacy rooted in integrity

CJI Gavai's speech examined the core values underpinning judicial legitimacy, contrasting the judiciary's authority, which derives not from the ballot but from public confidence, with the powers of the executive and legislature. "In every democracy, the judiciary must not only dispense justice, but also be seen as an institution that deserves to hold truth to power," he said, highlighting that the terms "judicial legitimacy" and "public confidence" are interconnected.

He cited BR Ambedkar's comments during the Constituent Assembly debates that the judiciary must remain "independent of the executive" and "competent in itself." Article 50 of the Constitution, Gavai noted, mandates the separation of the judiciary from the executive in public services, and mechanisms like fixed retirement ages, financial independence, and the collegium system were designed to uphold this principle.

The CJI reaffirmed the importance of judicial review and the judiciary's counter-majoritarian role. "Courts must have the power of independent judicial review," he said, citing the Supreme Court's landmark decisions that reinforced the supremacy of constitutional values over political expediency.

The CJI highlighted recent transparency initiatives by the Supreme Court, such as the live-streaming of Constitution Bench hearings and the public disclosure of judges' assets. "These are significant steps to bolster public confidence through transparency. Judges, as public functionaries, are accountable to the people."

While acknowledging that "no system is immune to flaws," he emphasised that "solutions must never come at the cost of judicial independence."

"Judges must be free from external control," said the CJI, calling for renewed commitment to reasoned judgments, recusal practices in case of conflicts of interest, and ethical leadership from the top.

Free Press Journal

`No Culprit Will Be Allowed To Escape': NHRC Member Priyank Kanoongo On Chinnaswamy Stadium Stampede In Bengaluru

The incident occurred outside the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru on Wednesday as an estimated crowd of over 2 lakh people gathered to celebrate RCB's first-ever IPL title win.

https://www.freepressjournal.in/india/no-culprit-will-be-allowed-to-escape-nhrc-member-priyank-kanoongo-on-chinnaswamy-stadium-stampede-in-bengaluru

IANS Updated: Wednesday, June 04, 2025, 09:32 PM IST

New Delhi: In the wake of the tragic stampede that claimed 11 lives during Royal Challengers Bangalore's IPL victory celebrations in Bengaluru, National Human Rights Commission (NHRC) Member Priyank Kanoongo expressed deep concern and vowed accountability in a public statement.

Taking to X, Kanoongo wrote: "The incident of the death of innocent people in the stampede during the celebration of victory in the IPL cricket tournament in Karnataka is very sad. The incident is being taken cognisance of, the responsibility of the culprits will be fixed after investigation, and no culprit will be allowed to escape. Citizens are requested to send information about the injured and dead directly to me by email, and participate in helping the victims. Information of any victim should not be hidden, and it is our duty to get them justice."

The incident occurred outside the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru on Wednesday as an estimated crowd of over 2 lakh people gathered to celebrate RCB's first-ever IPL title win.

The crowd overwhelmed the stadium's official 35,000-person capacity, leading to panic and a fatal stampede near the main gates.

The Karnataka government has confirmed that 11 people, mostly young girls and boys, lost their lives, while 33 others were injured, though all are now reported to be out of danger.

Addressing the press later that evening, Chief Minister Siddaramaiah termed the incident a "big tragedy" and visited the injured at Bowring and Vaidehi hospitals.

"One lakh people gathered in front of Vidhana Soudha. The capacity of Chinnaswamy Stadium is 35,000, but about 2 to 3 lakh people gathered at the stadium. No one expected this turnout," he said.

"Among the dead, most are young girls and boys. We are providing Rs 10 lakh compensation for each deceased's family. The injured will receive free treatment."

Siddaramaiah maintained that the situation was unforeseen and stressed that a magisterial inquiry would reveal if there were lapses in planning or security. The report is expected within 15 days.

When questioned by journalists on whether his remarks absolved the administration, Siddaramaiah responded sharply:

“The media should not ask questions like an opposition party… I don’t want to play politics in this. Let us wait for the outcome of the probe.”

The incident has already triggered a wave of criticism from opposition parties, particularly the BJP, over alleged administrative failure. However, the Chief Minister reiterated his focus on accountability over politics.

(Except for the headline, this article has not been edited by FPJ's editorial team and is auto-generated from an agency feed.)

Inshort

Administration’s negligence, will investigate: NHRC on stampede

https://inshorts.com/en/amp_news/administration-s-negligence--will-investigate--nhrc-on-stampede-1749058928558

National Human Rights Commission (NHRC) Member Priyank Kanungo said the Bengaluru stampede occurred due to negligence of the administration. "People were called, and due to a lack of adequate security arrangements, many people died...We will investigate this incident," he added. At least 11 people died and over 50 were injured in the stampede, which occurred outside Chinnaswamy Stadium.

Amar Ujala

Fatehabad News: कानूनगो ने सुनीं 23 शिकायतें, 15 का समाधान, आठ पर दिल्ली से कार्रवाई

https://www.amarujala.com/haryana/fatehabad/23-complaints-came-to-the-court-of-national-human-rights-commission-member-priyank-kanungo-action-will-be-taken-on-8-from-delhi-fatehabad-news-c-127-1-ftb1001-134987-2025-06-04

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 04 Jun 2025 11:44 PM IST

भूना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बुधवार को गुरु दक्ष प्रजापति धर्मशाला में जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत जनता दरबार लगाया। इसमें नागरिकों की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में कुल 23 शिकायतें आईं, इनमें से 15 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। आठ शिकायतों पर कानूनगो ने दिल्ली जाकर कार्रवाई का भरोसा दिया।

जनता दरबार में टोहाना के कुलभूषण सिंगला ने शिकायत देते हुए कहा कि डीएसपी, एसपी और डीजीपी को शिकायत देने के बावजूद भी उन पर जानलेवा हमला करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। उन्होंने डीएसपी, एसपी फतेहाबाद और डीजीपी ऑफिस तक सबूत दिए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। जांडलीखुर्द गांव के रोहताश कुमार और उनकी पत्नी ने भी शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई और गांव की एक लड़की ने प्रेम विवाह किया। इसके बाद गांव के दबंगों ने उनके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर गांव से निकाल दिया। जबकि उनका प्रेमी जोड़े से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उनके घर में आग लगा तोड़फोड़ की गई और बूढ़े पिता की पिटाई की गई।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने दबंगों के दबाव में आकर मामले को दबा दिया। प्रियंक कानूनगो ने इस मामले में भी दोबारा कार्रवाई का आश्वासन दिया। थानाध्यक्ष सुरेंद्रा ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा विवरण कानूनगो के सामने रखा।

कार्यक्रम के संयोजक और राष्ट्रीय बाल आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने कानूनगो का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कानूनगो ने पिछड़ा वर्ग की समस्याएं सुनीं और उन्हें जागरूक किया। कार्यक्रम में कुम्हार सभा के प्रधान जिले सिंह जाखड़, भीम सिंह झींझर, पार्षद सुशील सोनी, रोहतास गोयल, नरेश सोनी, प्रकाश कुमार आदि मौजूद रहे।

गोल्ड मेडलिस्ट दो महिला खिलाड़ियों को किया सम्मानित

News Nation

बेंगलुरु हादसा : भगदड़ में मासूमों की मौत पर प्रियंक कानूनगो ने लिया संज्ञान, न्याय का वादा

https://www.newsnationtv.com/bengaluru-hadsa-bhagdad-mein-masoomon-ki-maut-par-nhrc-ne-liya-sangyan-nyay-ka-vada--20250604213907/

IANS | 04 Jun 2025 23:25 IST

बेंगलुरु, 4 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के बेंगलुरु में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में कई मासूमों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। इस घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने दुख जताया है।

प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कर्नाटक में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की जीत के जश्न में भगदड़ होने से मासूम लोगों की मृत्यु की घटना बेहद दुखद है। इस घटना के दोषियों की जिम्मेदारी तय करने हेतु जांच करने के लिए घटना का संज्ञान लिया जा रहा है, किसी भी दोषी को बचने नहीं दिया जाएगा।

कानूनगो ने लिखा, नागरिकों से विनती है कि घायलों और मृतकों की सूचना सीधे मुझे ईमेल (priyank.kanoongo@gov.in) पर प्रेषित कर पीड़ितों की मदद में सहभागी बनें। किसी भी पीड़ित की जानकारी छिपाई न जा सके, उसको न्याय मिल सके, यह हम सबका कर्तव्य है।

उल्लेखनीय है कि चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 अन्य लोग घायल हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम मोदी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं, वे जल्द स्वस्थ हो जाएं।

बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दुख जताया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है और 33 लोग घायल हुए हैं। सीएम सिद्धारमैया ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही राज्य सरकार घायलों को मुफ्त इलाज भी मुहैया कराएगी।

--आईएएनएस

पीएसके/एकेजे

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

News9Live

Muzaffarpur Rape Case: Congress Protesters march to Health Ministe's home

Congress leaders and workers protested in Patna, Bihar, demanding justice for an 11-year-old Dalit girl raped and killed in Muzaffarpur. The demonstration, which began at Haj Bhawan and ended at Health Minister Mangal Pandeys residence, criticised alleged medical negligence and delayed action. Protesters displayed anger, with some throwing paint at Pandeys poster. The NHRC has issued notices to Bihar officials, and hospital staff have been suspended.

https://www.news9live.com/videos/india-videos/muzaffarpur-rape-case-congress-protesters-march-to-health-ministers-home-2862835

Aditi Saraswat Published: 04 Jun 2025 16:51:PM

New Delhi: A large-scale protest took place in Patna, Bihar, organised by the Congress party. The demonstration followed the rape and death of an 11-year-old Dalit girl in Muzaffarpur. Congress leaders and workers marched from the Haj Bhawan to the residence of Bihar Health Minister Mangal Pandey, expressing outrage at alleged medical negligence and the government's delayed response. Protesters carried signs, some depicting Rahul Gandhi, and others bearing Hindi slogans.

Some demonstrators engaged in confrontational behaviour, including throwing black paint at a poster of the Health Minister. The National Human Rights Commission (NHRC) has since issued notices to Bihar officials, and several hospital staff members have been suspended. The incident has sparked widespread anger and calls for justice across Bihar.

Tejashwi Yadav, the Leader of the Opposition in the Bihar Legislative Assembly, visited a child's home in Muzaffarpur on Tuesday, June 3, 2025. He criticised the state government for the child's death due to negligence and the alleged failure of law and order in the state. Mr. Yadav also attacked Bihar Chief Minister Nitish Kumar, claiming that beds in government hospitals are sold at premium prices.

Live Law

UP Court Orders Action Against Cops Who Allegedly Subjected Accused To Custodial Violence, Had Him Bitten By Dog

https://www.livelaw.in/news-updates/up-bareilly-court-action-up-police-cops-accused-custodial-violence-bitten-dog-294215

4 June 2025

An ACJM court in Uttar Pradesh's Bareilly district on Monday directed action against certain UP Police officials who allegedly subjected an accused to custodial violence and had him bitten by a dog.

Terming the alleged acts of violence to be "a very serious matter", Additional Chief Judicial Magistrate Amir Sohail directed the Senior Superintendent of police, Bareilly, to get the case properly investigated and take necessary action against the erring police officials and to inform the court about the action taken against them.

The Court also directed that an inquiry be conducted against a doctor of the District Hospital who examined the accused medically and allegedly prepared a misleading and false medical report, hiding the injuries of the accused.

The court also directed the District Magistrate, Bareilly, to ensure at his level that no violence of any kind is committed against the 4 accused during their judicial custody.

The court passed these directions while dealing with a remand application concerning the accused (Bilal, Sohail, Rahmuddin and Asif) booked under Sections 109, 352, 3 (5) BNS and Sections 3, 25 and 27 of the Arms Act, 1959.

Essentially, before the Court, an application was submitted on behalf of the accused Bilal stating that the police officers who arrested him had injured him while in custody, specifically on his thumb, the wrists of both hands, and his back, using a belt and a lathi.

He also alleged that the police made a dog bite him in two places on the side of his waist. His counsel also claimed that injuries were present on various parts of his body, all allegedly caused by the police and submitted that the doctor who conducted the medical examination ignored these injuries in his report.

Similarly, three other accused also alleged that they had been beaten by the police. They showed injuries on their bodies to the Court and alleged they had been kept at the police line continuously since the day of their arrest.

Taking into account the allegations levelled against the police officials, and the visible injuries, particularly those of accused Bilal, who had clear marks of animal bites on his waist, the Court concluded that there were obvious signs of violence committed while the accused were in police custody.

ACJM also observed that the accused had been beaten up and injured, but the doctor who conducted the medical examination failed to report these injuries.

Regarding the animal bite marks on the body of accused-Bilal, the Court called it the most inhumane of all the injuries, noting that the wounds appeared to have been caused by an animal, likely a dog.

Calling the case a "very serious" one, the Court held that there was a violation of the Supreme Court guidelines laid down in D.K. Basu v. State of West Bengal [1997] and Joginder Kumar v. State of Uttar Pradesh [1994] concerning custodial violence.

Furthermore, the Court termed the incident a "live example" of custodial violence and deemed it necessary to get the roles of the arresting officer, the investigating officer, and the doctor who conducted the medical examination, be investigated so that action could be taken against them.

Accordingly, while passing the above-mentioned directions for appropriate inquiry, the Court also directed that a copy of its order be sent to the National Human Rights Commission, New Delhi, and the Uttar Pradesh State Legal Services Authority, Lucknow.

Lastly, the Court remanded the accused to judicial custody until 16 June.

Rising Kashmir

Four-fold Doctrine for Return & Resettlement of the Exiled Pandits

There can be no return and resettlement without dignity and without homeland

https://risingkashmir.com/four-fold-doctrine-for-return-resettlement-of-the-exiled-pandits/

Last updated: June 4, 2025 1:36 am | ASHWANI KUMAR CHRUNGOO

Published: June 4, 2025

12 Min Read

FRAGRANCE OF IDEAS

Over the last some weeks some frivolous activity in the name of the return and resettlement of the Kashmiri Pandit community in the valley of Kashmir has been observed. It is believed that this doubtful activity on behalf of a few among the displaced community is being sponsored by some extraneous forces outside the community.

Though this activity has no mass support within the exiled community yet it has been promoted to be seen as an integral part of the community activism; and the auspicious occasion of Mela Khirbhawani has been chosen to showcase the so-called support to this isolated activity. However, it has again forced the displaced community to express its firm resolve on the issue of return and resettlement in an unambiguous manner. It is time to reflect on this issue in appropriate detail.

On behalf of the community that has been living as refugees in its own country for the last more than 35 years due to the ethnic cleansing in the valley of Kashmir, an all-party meeting of the community representatives was held in the capital of the country -New Delhi last Sunday. All participating representative members rejected the so-called activity by a few in the name of the return and resettlement in Kashmir ab initio.

This author was also one of the participants in the important meeting. It was further resolved in the conclave that the displaced community has a firm and unwavering commitment and faith in the historical Resolutions passed by the community from time to time in regard to the issue of return and resettlement in the valley of Kashmir.

The representatives unanimously rejected all attempts to subvert the narrative of genocide of the community and expressed firm resolve in the Margdarshan resolution and the other resolutions passed in the spirit of this historic resolution. It needs to be made clear here that there are four major historic resolutions passed from time to time that have been guiding the displaced community in this context for the last 35 years of exile. Margdarshan resolution on Homeland is the lead resolution in this regard.

Immediately after the forced mass-exodus of the Hindu community of Kashmir consequent upon the acts of genocide committed against them, the thinking minds and

the prominent activists of the exiled community in May-June 1990 thought of reviving the oldest Kashmiri Pandit forum -All State Kashmiri Pandit Conference (ASKPC) in Jammu.

The first important decision it took was to convene a two-day convention of the exiled community representatives to deliberate upon the issue of the mass exodus and the future existence of the displaced community. This author being a part of its Executive in 1990 was also a member of the Organising Committee for the Convention called Kashmiri Hindu Convention 1990 and held the responsibility of Treasurer in the new set-up.

Accordingly, the two-day Convention was held in the scorching heat of Jammu on 13-14 July, 1990 in the Central Mahajan Sabha Hall, City Chowk. The congregation was attended by more than 500 delegates from all over India and it was resolved (under Resolution no. 4) to demand the carving out of a security zone in the valley of Kashmir for the Kashmiri Pandit community with constitutional guarantees so that the exiled community could be resettled back in the valley of Kashmir that historically belonged to them as the indigenous people of the place.

The convention also unanimously condemned the human rights violations committed against the community in Kashmir by the Islamic terrorist and radical forces and asked the government to provide armed licenses to the Kashmiri Pandits in the valley along with the facilities of training in the use of arms for their safety and security in the valley.

This was followed by a vigorous public contact drive by the younger elements among the Kashmiri Pandit activists in support of the Resolution that was overwhelmingly supported by the entire community. It ultimately led to the establishment of Panun Kashmir on 31st December 1990 at Raghunathpura, Jammu with the aim of propounding the cause of the exiled community in a socio-political framework.

Panun Kashmir organised a huge convention named Margdarshan at Jammu on 27-28 December 1991 in Abhinav Theatre, Jammu. It was attended by nearly 1,000 delegates of the exiled community from all over the world supported by a large number of nationalist campaigners from outside the community as well.

Margdarshan Convention 1991 adopted a historic resolution calling for the establishment of Homeland with Union Territory status in Kashmir for the seven lakh displaced Hindus of Kashmir who yearn to return and resettle in Kashmir. It was also resolved in the resolution that the Indian constitution may be fully applicable in the Union Territory in letter and spirit.

The Resolution in its context explained how coexistence was refused to the displaced Kashmiri Pandit community all along in the past, forcing the members of the community to leave Kashmir in peace meals earlier to the mass-exodus of 1989-90. It also said that Pakistan & Pak-sponsored terrorism in collaboration with extremism and fundamentalism in the valley were responsible for the brutal killings and other human rights violations of the exiled community in Kashmir.

Ten years after the mass exodus, on the historic 13 July 2000, various representative bodies of the Kashmiri Pandit community organised the one-day Kashmiri Pandit Representative Assembly in the hall of the Mansar Hotel in Jammu. It discussed the socio-political scenario concerning the community in detail and unanimously adopted a resolution asking for a separate state for the displaced Kashmiri Hindus in the valley of Kashmir.

Representatives of the main community forums like ASKPC, Panun Kashmir, AIKPC, AIKS and other important organisations attended the conference headed by the veteran Pt. Amarnath Vaishnavi. It also issued an appeal to the community to rally round the community's unanimous voice in this regard expressed through the spirit of the three historic resolutions adopted from time to time.

Again in 2014-15, the Kashmir District Displaced Unit of BJP in its convention at KK Resorts, Jammu adopted a resolution in which it resolved to demand a one-place settlement in the Kashmir valley for the exiled community of Kashmiri Pandits. The officials of the Unit and the organisers of the Convention presented the historic resolution formally to their higher ups in the BJP headquarters in Jammu after the event.

All the above-mentioned four historic resolutions assume great significance in the struggle in exile of the Kashmiri Pandits so far as their issues pertaining to the return and resettlement in the valley are concerned. This author consistently has been espousing the cause of the unanimous resolve of the community in this context besides advocating the issues pertaining to our human rights violations, genocide and ethnic cleansing in Kashmir. In regard to our forced mass-exodus, I have been consistently holding the following four factors responsible for the exodus of the Kashmiri Pandit community in 1989-90. These are:

The fundamentalist and terrorist elements in Kashmir supported and abetted by Pakistan (both the so-called state and the non-state actors), complicity of the then J&K government with the separatist and radical elements in the society in Kashmir valley, failure of the Muslim majority community to provide safety to the miniscule minority community of Hindus in Kashmir and the unpardonable failure of the government of India continuously from 1947 to protect the minorities in Jammu and Kashmir. These four factors together brought the Kashmiri Pandit community, the indigenous people of the valley, to the roadside in and after 1989-90 due to the mass-exodus.

The struggle in exile of the community, hundreds and thousands of meetings and programmes held during these 35 years of exile and our unabated struggle before the human rights bodies including the **National Human Rights Commission (NHRC),** parliamentary forums, internationals bodies and the media evolved a four-fold doctrine for our return and resettlement in Kashmir.

The main features of this doctrine are the following:

The Kashmiri Pandit community will neither forget nor forgive what was done to them in the Kashmir valley,

Genocide of Hindus in Kashmir is a non-negotiable issue and the **NHRC** has put it on record that “acts akin to genocide were committed against the Kashmiri Pandits in Kashmir….and a genocide type design may exist in the minds and utterances of the militants and terrorists in Kashmir against the Kashmiri Pandits”,

There can be no reconciliation without proper justice and punishment to the perpetrators of the crimes against humanity and

There can be no return and resettlement without dignity and without homeland.

This four-fold doctrine is not only the essence of our struggle in exile but it is the only guarantee in regard to what was done to the community and that history won’t be repeated in Kashmir with the Kashmiri Pandit community, the original inhabitants of the Kashmir valley.

The deliberate attempts to distort the Kashmiri Pandit genocide narrative, float fabricated one-upmanship, and bypass the community’s core ideological aspiration will meet the same end that all such earlier attempts have met in the past…!

ETV Bharat

हजारीबाग में बिरहोर मौत के साये में गुजार रहे जिंदगी, कोयला खदान के पास है टंडा - BIRHOR TRIBE

हजारीबाग के केरेडारी में बिरहोर जनजाति के लोगों की हालत बेहद दयनीय है. जिंदा तो हैं, लेकिन कब तक मालूम नहीं.

https://www.etvbharat.com/hi/!bharat/condition-of-birhor-tribe-people-in-hazaribag-keredari-is-very-pathetic-hindi-news-jhn25060404696

By ETV Bharat Jharkhand Team | Published : June 4, 2025 at 5:54 PM IST

5 Min Read

हजारीबागः बिरहोर विलुप्त होती हुई जनजाति है, जिसे संरक्षित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं धरातल पर उतारी हैं. लेकिन इन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, यह हजारीबाग के केरेडारी में जाने से पता चलता है. ईटीवी भारत की टीम यहां गई और देखा कि किस तरह लगभग 32 बिरहोर परिवार मौत के साये में जी रहे हैं.

दरअसल पास में ही एनटीपीसी के कोल माइंस के कारण इनका जीवन खतरे में है. कोल उत्खनन के कारण हो रहे ब्लास्ट और प्रदूषण के कारण इनका जीवन प्रभावित हो रहा है. मानवाधिकार आयोग के संज्ञान लेने के बाद भी अब तक जिला प्रशासन की नींद नहीं खुली है. हर दिन ये मौत से रूबरू हो रहे हैं.

हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत पगार में एनटीपीसी के कोल माइंस क्षेत्र में ही 32 बिरहोर परिवार निवास कर रहे हैं. जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए बिरहोर टंडा में ही इनका बसेरा है. बिरहोर टंडा से महज 50 मीटर की दूरी पर ही एनटीपीसी कोयला उत्खनन का काम कर रही है.

कोयला उत्खनन के कारण हर दिन यहां ब्लास्ट किया जाता है. जिस कारण बिरहोर के बने हुए घर भी क्षतिग्रस्त चुके हैं. पास में ही बिरहोर बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भी है. उस विद्यालय की भी स्थिति दयनीय है.

शिक्षिका भी बताती हैं कि दिनभर बड़ी-बड़ी गाड़ी कोयला लदी हुई गुजरती है. जिससे पूरे विद्यालय समेत बिरहोर के आवास में भी कोयले का डस्ट पहुंच जाता है. कपड़े और शरीर भी कोयले के डस्ट से सने रहते हैं. जब ब्लास्ट होता है तो घर भी हिल जाता है. जान जोखिम में डालकर छात्र स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उनके माता-पिता घर पर रहते हैं.

स्थानीय बिरहोर भी कहते हैं कि जिस जगह पर टंडा बनाया गया है, वहां कोयला का माइंस है. दिनभर कोयला उत्खनन होता है. रात में भी काम जारी रहता है. जिस कारण जीवन प्रभावित हो रहा है. विस्फोट और कोयले की धूल के कारण जीना दुभर हो रहा है. एनटीपीसी खाने के लिए भोजन तो उपलब्ध कराती है लेकिन उसके बदले में डस्ट भी मिलता है.

बिरहोर की स्थिति को लेकर समाजसेवी और स्थानीय निरंजन कुमार बताते हैं कि उनकी समस्याओं को लेकर कई बार पत्राचार किया गया है. हल अब तक नहीं निकल पाया है. दिन भर में 10000 से हाईवा गाड़ी

इनके कॉलोनी के सामने से गुजरती है. सबके डस्ट इनके घर और स्कूल तक पहुंचते हैं. 32 बच्चे विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यालय में भी छात्र सुरक्षित नहीं हैं.

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का यह क्षेत्र है. सांसद भी स्वीकार करते हैं कि बिरहोर एक ऐसी जनजाति है जिसे संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. आने वाले समय में कैसे पगार के बिरहोर को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए इसे लेकर वार्ता भी की जाएगी. अब बहुत जल्द समाधान भी होगा. उन्होंने ईटीवी भारत को कहा कि आपने यह मुद्दा संज्ञान में लाया है.

हजारीबाग के नवनियुक्त उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह को जब ईटीवी भारत की टीम ने पगार में जान जोखिम में डालकर बिरहोर रह रहे हैं इसकी जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि नियम कानून के अंतर्गत रहकर कदम उठाया जाएगा. इस संबंध में पहले भी बैठक की गई थी. इन्होंने जोर देते हुए कहा कि पहले भी कदम उठाया गया था. लेकिन कार्रवाई नहीं की गई. यह बहुत ही गंभीर मामला है. जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक कानून के दायरे में रहकर कोल उत्खनन कंपनी को काम करने कहा गया है.

एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना के कारण बिरहोर खतरे में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं. जरूरत है जिला प्रशासन को कदम उठाने की और इन्हें किसी दूसरे जगह स्थानांतरित करने की. ताकि इन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके.

हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना में खनन के दुष्प्रभाव से आदिम जनजाति समुदाय के किरणी बिरहोर और बहादुर बिरहोर की मौत हो गई थी. इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग को सम्मन जारी किया था.

उपायुक्त को आयोग के सामने दस फरवरी को व्यक्तिगत पेश होने को कहा गया था. दस फरवरी से पहले पूर्व में मांगे गए चार बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट भेज दी जाती है तो व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट मिलने की बात भी कही थी.

CG Khabar

18 साल बाद छत्तीसगढ़ के सलवा जुड़ूम की याचिका का हुआ निपटारा

https://cgkhabar.com/news/salwa-judum-case-final-verdict-20260604

June 4, 2025CG Khabar

रायपुर | संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद या विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी क़ानून न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता है. अदालत ने कहा कि किसी अधिनियम का सरल शब्दों में प्रवर्तन केवल विधायी कार्य की अभिव्यक्ति है और इसे न्यायालय की अवमानना नहीं कहा जा सकता, जब तक कि यह पहले स्थापित न हो जाए कि इस प्रकार से अधिनियमित किया गया कानून संवैधानिक रूप से या अन्यथा विधि की दृष्टि से गलत है. इस आदेश के साथ ही पिछले 18 सालों से सुप्रीम कोर्ट में सलवा जुड़ूम को लेकर लंबित याचिका का निपटारा कर दिया है.

गौरतलब है कि 2007 में समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के संरक्षण में चलाए जा रहे सलवा जुड़ूम पर रोक लगाने की मांग की थी. सलवा जुड़ूम में तत्कालीन रमन सिंह सरकार में आम आदिवासियों को नक्सलियों से लड़ने के लिए हथियार दे दिए गए थे.

बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो राज्य सरकार ने इन हथियारबंद लोगों को एसपीओ और कोया कमांडो के तौर पर बहाल करने की बात कही. इसके बाद 5 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुड़ूम को ग़ैरक़ानूनी बताते हुए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की और इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया. इसके बाद राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011 (“अधिनियम”) लागू कर इन सशस्त्र लोगों को नौकरी दे दी. इसे नंदिनी सुंदर ने अदालत की अवमानना बताते हुए एक और याचिका दायर की थी.

जुलाई 2011 में सुनाए गए आदेश, जिसमें एसपीओ की नियुक्ति रोकने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, सीबीआई जांच आदि मुद्दों पर निर्देश दिए गए थे. नंदिनी सुंदर की ओर से मांग की गई थी कि याचिकाओं में दाखिल सभी आवेदनों और अवमानना याचिका को सुनकर आवश्यक आदेश दिए जाएं. उनकी ओर से मांग की गई कि याचिकाएं लंबित रखी जाएं और उपयुक्त आदेश पारित किए जाएं.

लेकिन केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित एएसजी के.एम. नटराज ने तर्क दिया कि 05.07.2011 के आदेश की अनुच्छेद 96 में निर्धारित सभी रिपोर्टें दाखिल की जा चुकी हैं. इसलिए अब याचिकाओं को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है.

अदालत ने कहा कि याचिका में न्यायालय के आदेश की अवमानना पर कार्रवाई, एफआईआर नहीं होने तक SPO कर्मियों की सरकारी सेवा में नियुक्ति रोकने और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास योजना लागू करने की मांग की गई है. हमने पाया कि इन प्रार्थनाओं पर न्यायालय ने पहले ही आदेश पारित कर दिए हैं.

अदालत ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि पुनर्वास योजना दाखिल की गई है और नई विधायी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल है. NHRC द्वारा भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है. इस स्थिति में हम पाते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा ताकि शांति और पुनर्वास संभव हो सके.

अदालत ने कहा कि हालांकि, किसी विधेयक का पारित होना स्वतः न्यायालय की अवमानना नहीं होता जब तक कि वह असंवैधानिक घोषित न किया जाए. अगर किसी को ऐसा लगता है तो वह विधिक प्रक्रिया के तहत वैधता को चुनौती दे सकता है.

अवमानना याचिका में जो प्रार्थनाएं की गई हैं, वे वास्तव में रिट याचिकाओं में की जानी चाहिए थीं. अतः हम इस अवमानना याचिका पर आगे विचार नहीं कर सकते और इसे समाप्त करते हैं. रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थनाओं पर पहले ही निर्णय हो चुका है, अतः अब वे विचारणीय नहीं हैं. इसी तरह अनुच्छेद 96 के अंतर्गत मांगी गई रिपोर्टें भी प्रस्तुत की जा चुकी हैं.

याचिकाओं का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि NHRC द्वारा अनुपालना न करने की शिकायत अब विचारणीय नहीं है क्योंकि हम अब याचिकाओं का निपटारा कर रहे हैं. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में, रिट याचिकाएं और अवमानना याचिका समाप्त की जाती हैं. लंबित आवेदन भी समाप्त माने जाएं.

Amar Ujala

Charkhi Dadri News: नहरों में रसायन युक्त और जोहड़ों का दूषित पानी डालने पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

https://www.amarujala.com/haryana/charkhi-dadri/the-human-rights-commission-has-taken-notice-of-the-discharge-of-chemical-laden-and-contaminated-water-into-canals-and-ponds-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1001-138186-2025-06-04

अमर उजाला ब्यूरो | Updated Wed, 04 Jun 2025 11:58 PM IST

चरखी दादरी। जिले की मुख्य नहरों में रसायन युक्त और जोहड़ों का दूषित पानी डालने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इसकी दादरी परिषद से रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी और उससे एक सप्ताह पहले आयोग को रिपोर्ट भेजनी होगी। आयोग ने आदेश की प्रति शिकायतकर्ता व नगर आयुक्त को ईमेल व डाक के माध्यम से भेजी है।

बता दें कि संजीव तक्षक की अगुवाई में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने चरखी दादरी जिले की लोहारू फीडर और बधवाना माइनर जैसी प्रमुख नहरों में रसायन युक्त और गंदे पानी की निकासी करने का आरोप लगाकर एसडीएम को शिकायत सौंपी थी। अधिवक्ताओं ने बताया था कि ये नहरें शहर और कई गांवों में पेयजल आपूर्ति की जीवनरेखा है। जनस्वास्थ्य विभाग इन्हीं नहरों से पानी उठाकर जलघरों के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाता है, लेकिन इन नहरों में गंदा पानी डालने से पानी में रसायन, जहरीली दवाइयों के अंश, साबुन-सर्फ, और अन्य दूषित पदार्थ मिल जाते हैं। दूषित पानी पीने से लोग कैंसर, त्वचा रोग, दमा और टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।

तीन विभागों पर लापरवाही बरतने का आरोप

शिकायत में बताया गया था कि जनस्वास्थ्य, सिंचाई विभाग व बिजली निगम की लापरवाही के चलते नहरों में गंदा और जहरीला पानी डाला जा रहा है। यहां तक कि कुछ स्थानों पर पाइप लाइन को दबाकर और हाईवोल्टेज बिजली लाइन डालकर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है।

संबंधित अधिकारियों को जारी किए नोटिस

अधिवक्ताओं ने शिकायत के माध्यम से चेताया था कि यदि प्रशासन ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह समस्या जिले के निवासियों व पशुओं के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता मोहित की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम चरखी दादरी के आयुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है।

प्रशासन से की पानी निकासी बंद कराने की मांग

अधिवक्ताओं ने प्रशासन से नहरों में गंदा और रसायन युक्त पानी डालने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेताते हुए कहा कि यदि अब भी समाधान नहीं किया गया तो वे इस मुद्दे को सिविल कोर्ट और आवश्यक हुआ तो उच्च न्यायालय तक भी लेकर जाएंगे।

ड्रेन बनाकर सरकार करे समाधान

अधिवक्ता संजीव तक्षक ने बताया कि सरकार व प्रशासन को बार-बार पत्र लिखकर गंदे पानी की निकासी के लिए एक अलग से ड्रेन बनाने की मांग कर चुके हैं। एनजीटी ने भी राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि नहरों में गंदा पानी न डाला जाए, उसके बावजूद भी प्रशासन आदेश का पालन नहीं करवा रहा।

Jagran

शर्मिष्ठा के खिलाफ FIR करवाने वाले को गिरफ्तार करेगी असम पुलिस, NHRC ने भी दिए इंफ्लुएंसर की सुरक्षा के आदेश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर शर्मिष्ठा पनौली की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है जिन्हें पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शर्मिष्ठा को दुष्कर्म और हत्या की धमकियां मिली हैं। वहीं शर्मिष्ठा के खिलाफ FIR करवाने वाले वजाहत खान कादरी रशीदी को गिरफ्तार करने असम पुलिस कोलकाता आ रही है।

https://www.jagran.com/west-bengal/kolkata-times-of-india-kolkata-man-who-filed-fir-against-instagram-influencer-sharmishta-panoli-now-23956137.html

By Jagran NewsEdited By: Swaraj SrivastavaUpdated: Wed, 04 Jun 2025 11:21 PM (IST)

HighLights

उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का आरोप

अलीपुर महिला जेल में न्यायिक हिरासत में शर्मिष्ठा

30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार हुई थी शर्मिष्ठा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार इंटरनेट मीडिया एंफ्लुएंसर व कानून विषय की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।

शर्मिष्ठा इस वक्त कोलकाता की अलीपुर महिला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। शर्मिष्ठा को दुष्कर्म व हत्या की धमकियां मिल चुकी हैं। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा- 'हमें लीगल राइट्स आब्जर्वेटरी नामक संगठन से शिकायत मिली है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के समय उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।

30 मई को गुरुग्राम से हुई थी गिरफ्तारी

उन्होंने कहा कि 'शर्मिष्ठा को धमकियां मिलने की भी जानकारी दी गई है। इसे देखते हुए हमने बंगाल के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक व डीजीपी को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।' मालूम हो कि शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने गत 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था।

उनके विरुद्ध वजाहत खान कादरी रशीदी नामक व्यक्ति ने गत 15 मई को कोलकाता के गार्डेनरीच थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस बीच शर्मिष्ठा के पिता पृथ्वीराज ने बंगाल सरकार व पुलिस के उस दावे को सिरे से नकारा है कि उनकी बेटी गिरफ्तारी से पहले गुरुग्राम से फरार हो गई थी। उन्होंने पुलिस पर शर्मिष्ठा के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की प्रति नहीं देने का भी आरोप लगाया है।

वजाहत को गिरफ्तार करने रही असम पुलिस

वजाहत को गिरफ्तार करने असम पुलिस की एक टीम कोलकाता आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में तीन पुलिसकर्मियों की टीम इस बाबत बुधवार को गुवाहाटी से रवाना हुई है। कोलकाता पहुंचकर वह वजाहत को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

वजाहत पर मां कामाख्या के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में असम पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने वजाहत को कानूनी कार्रवाई के लिए असम लाने में बंगाल सरकार से सहयोग करने को कहा है।